

आरबीआई के कार्य में सांख्यिकी और सांख्यिकीय विश्लेषण *

दुव्वुरी सुब्बाराव

आरबीआई में सांख्यिकी दिवस

सांख्यिकी दिवस सम्मेलन, जो सांख्यिकी के क्षेत्र में समादृत प्रो.पी.सी.महालनवीस की स्मृति में मनाया जाता है, रिजर्व बैंक के वार्षिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में अंकित है। चूँकि सांख्यिकीय विश्लेषण रिजर्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण निविष्टि होता है, जिससे यह प्राप्त अधिदेश के अनुसार कार्य-निष्पादन कर सकता है, हमारे लिये यह वार्षिक सम्मेलन एक मूल्यवान ज्ञानार्जन अनुभव होता है।

2. मैं यहाँ अर्थशास्त्र में सांख्यिकीय विश्लेषण के क्षेत्र में अग्रणी अनेक विशेषज्ञों को उपस्थित देख रहा हूँ : प्रो.आर.राधाकृष्ण, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग; डॉ. ऑरेल शूबर्ट, महानिदेशक, युरोपियन सेंट्रल बैंक; प्रो. जे.आर.वर्मा, आईआईएम, अहमदाबाद; प्रो.प्रबाल चौधरी, आईएसआई, कोलकाता; और प्रो. अमित बुबना, आईएसबी, हैदराबाद। एक बार फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ।

वास्तविक विश्व की सांख्यिकी में अंतर्निहित अनिश्चितता

3. हम यह जानते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनिश्चितता अंतर्निहित होती है, जहाँ निष्कर्षों को मानवीय व्यवहार द्वारा आकार दिया जाता है। जैसाकि मैंने अन्य अवसर पर कहा था, मैं अपने व्यवहार से किसी इलेक्ट्रॉन के भार को परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपने व्यवहार द्वारा किसी डेरिवेटिव के मूल्य में परिवर्तन लाने की उम्मीद रख सकता हूँ। संकट के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों के विरुद्ध एक आरोप यह लगाया जाता है कि वे 'फिजिक्स एनवी' से ग्रस्त थे, जिसने उन्हें रमणीय मॉडल बनाने दिये, जिसके लिए उन्होंने परिष्कृत गणितीय एवं प्रभावोत्पादक सांख्यिकीय चतुराई का प्रयोग किया और स्वयं को तथा पूरी दुनिया को धोखे में रखा कि उनके मॉडलों में अधिक परिशुद्धता और भविष्यसूचक शक्ति है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं था। परिशुद्धता की इस विभ्रान्त खोज में जिस तथ्य को भुला दिया गया था, वह यह था कि आर्थिक निष्कर्ष मानवीय व्यवहार का एक कृत्य होता है, जो अर्थशास्त्र की एक मौलिक धारणा के विपरीत,

* 17 जुलाई 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई में छठे वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन के अवसर पर डॉ.दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

हमेशा युक्तिसंगत नहीं होता है। यह भी कि आर्थिक प्रणालियाँ इस अर्थ में सोच पर निर्भर करती हैं कि किसी घटना के घटित होने का विश्वास होना अक्सर घटित होने वाली घटना को प्रभावित करता है।

4. 'गॉड पार्टिकल' की खोज की हाल की घोषणा में - दि हिग्स बोसोन - युरोपियन लैब, सर्न, ने कहा था कि निश्चितता का इसका स्तर 4.9 सिग्मा है, जिसका तात्पर्य यह है कि भौतिक शास्त्री आकर्षक रूप से 'गोल्ड स्टैंडर्ड (5 σ)' के निकट पहुँच गये - या इस परिणाम के यादृच्छिक रूप से घटने-बढ़ने या कोलाहल का 2 मिलियन में से एक अवसर उपस्थित हुआ।

5. हम आर्थिक वैरिएबलों के सांख्यिकीय अनुमान में ऐसी परिशुद्धता के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते, जहाँ त्रुटियाँ अनेक स्रोतों से उत्पन्न हो सकती हैं, यथा, रिपोर्टिंग में भूल, आँकड़ों के संचयन में भूल, वैरिएबलों के बीच संबंध के मापन में भूल, आदि। दूसरे शब्दों में, आर्थिक घटनाओं के मूल्यांकन में अनियमितता से धोखा खाने के अवसर ज्यादा होते हैं। यह आर्थिक आँकड़ों से सही संकेतों का अर्थ निकालना है और मनोवांछित संकेतों को अलग निकालना है, अर्थात्, अप्रामाणिक कोलाहल से, जो अधिक जटिल होते हैं, प्रवृत्तियों और चक्रों को अलग करता है। इन सबों से यह सीख मिलती है कि आर्थिक विश्लेषण के लिए आँकड़े एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने तथा निर्वचन करने में हमें उनमें अंतर्निहित अशुद्धियों पर ध्यान रखना चाहिए।

आँकड़ा अंतराल और केंद्रीय बैंक

6. इस वर्ष के सम्मेलन की विषय-वस्तु है 'आँकड़ा अंतराल और केंद्रीय बैंक'। यह एक ऐसा विषय है, जो सर्वकालिक रूप से मान्य होता है और एक ऐसा विषय भी है, जिसे हमारी जाँच सूची में हमेशा होना चाहिए। मेरा मानना है कि इस विषय-वस्तु के पीछे प्रेरणा वैश्विक वित्तीय संकट से प्राप्त हुई है, जिसे पिछले पाँच वर्षों से हम झेल रहे हैं। संकट के इस संदर्भ में अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्माताओं के बारे में मुख्य रूप से तीन प्रकार की आलोचना की गयी; कि उन्होंने संकट उत्पन्न करने में मदद की, संकट के आगमन को महसूस करने में वे विफल हुए और कि उनके पास इस संकट के समाधान के लिए कोई योजना नहीं है।

7. आइए, हम इन प्रश्नों को आँकड़ा एवं सांख्यिकीय विश्लेषण के संदर्भ में देखें। क्या संकट के पीछे आँकड़ा अंतराल और सांख्यिकीय

मापन में कमियाँ थीं? क्या आँकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन इतने बिगड़े और पक्के थे कि संकेतों को पहचाना नहीं जा सका? क्या आँकड़ा अंतराल और आँकड़ा विश्लेषण संकट-प्रबंधन में बाधक बनते हैं? इन तीनों प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर यह है कि जबकि आँकड़ा अंतराल के कारण संकट उत्पन्न नहीं हुआ हो सकता है, संकट ने अनेक आँकड़ा अंतरालों को प्रकट किया। इसी प्रकार, आँकड़ों के मापन, विश्लेषण और निर्वचन में कमियों ने युक्तियुक्त और समय पर प्रतिक्रिया करने में अवरोध उत्पन्न किया। जैसाकि बीआईएस के क्लॉडियो बोरियो ने कहा था 'संकट उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह नहीं है कि सांख्यिकी में कोई कमी है, लेकिन उनके सही निर्वचन में विफल होना और उपचारात्मक कार्रवाई नहीं करना मुख्य कारण होता है।'

क्या हमने पिछले संकटों से कुछ सीखा है?

8. चूँकि वैश्विक वित्तीय संकट का हमारी सजगता से बहुत हद तक संबंध होता है, अतः एक प्रासंगिक मुद्दा यह होता है कि क्या सांख्यिकीविदों ने पिछले संकटों से कुछ सीखा है? जैसाकि राष्ट्रपति ओबामा के एक सलाहकार ने कहा था 'यह संकट इतना अच्छा है कि इसे व्यर्थ नहीं माना जाना चाहिए'। यह उक्ति ऐसी है, जिस पर आर्थिक सांख्यिकीविद हमेशा से सतर्क रहते आये हैं।

9. 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने आर्थिक विश्लेषण के लिए एक नये सांख्यिकीय ढाँचे के विकास की अगुआई की थी। जैसाकि युएन स्टैटिस्टिकल कमीशन¹ ने टिप्पणी की थी, विश्वव्यापी मंदी ने राष्ट्रीय लेखों को जन्म दिया और उनका विकास आर्थिक कार्यकलाप के एक संगत एवं व्यापक उपाय के रूप में नीति-निर्माताओं के लिए किया गया था। विश्वव्यापी मंदी के पाठ ने सांख्यिकीय रूप से अनुमानित समष्टिआर्थिक कालमान श्रेणी मॉडलों का विकास टिन्वर्जेन और हैवेलमों जैसे द्वारा कराया था, हालाँकि इस दृष्टिकोण की आलोचना कीन्स द्वारा की गयी थी, जिसकी इस मॉडल और पद्धति के बारे में अपनी शंकाएँ थीं (सिम्स, नोबेल लेक्चर, दिसंबर 2011)।

10. अभी हाल ही में लैटिन अमरीकी वित्तीय संकट के बाद, आईएमएफ ने आर्थिक एवं वित्तीय सांख्यिकी की पारदर्शिता का संवर्धन करने के लिए आँकड़ा मानक उपक्रमण आरंभ किये, जिसमें वर्ष 1996 में शुरू किये गये विशेष आँकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) और वर्ष 1993 में शुरू की गयी सामान्य आँकड़ा प्रसार प्रणाली (जीडीडीएस) शामिल हैं। इनका लक्ष्य था समय पर और व्यापक सांख्यिकी का उपलब्ध होना, जो समष्टिआर्थिक नीतियाँ तैयार करने में योगदान करती। इससे पूर्व इस वर्ष आईएमएफ ने अपने आँकड़ा मानक उपक्रमणों के अपर टीयर के रूप में एसडीडीएस

प्लस निकाला, जिसका विशिष्ट लक्ष्य था, वैश्विक संकट के दौरान पहचाने गये आँकड़ा अंतरालों पर ध्यान देना।

11. वैश्विक संकट, जो वर्ष 2008 में आरंभ हुआ था, और जो अभी भी हमारे साथ है, ने जी-20 देशों के छत्र के नीचे एक सामूहिक उपक्रमण को प्रेरित किया था, ताकि आँकड़ा अंतराल के मुद्दे पर ध्यान दिया जा सके। जी-20 आँकड़ा अंतराल उपक्रमण का लक्ष्य है वित्तीय क्षेत्र में जोखिम निर्मिति, सीमापार संबद्धताओं, आघातों के प्रति घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की असुरक्षा और अनेक क्षेत्रों की अंतर्संबद्धता के संबंध में आँकड़ा अंतराल को पाटना और सरकारी सांख्यिकी की सूचना और प्रसार में सुधार लाना। अनेक अंतरराष्ट्रीय निकाय, जिनमें युनाइटेड नेशन्स इंटर एजेंसी ग्रुप, आईएमएफ, एफएसबी, ओईसीडी, सीआईएल और ईसीबी शामिल हैं, इस अभ्यास में लगे हैं।

12. आँकड़ा अंतरालों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बाँटा गया है; पहली श्रेणी उन अंतरालों की है, जिनके लिए एक वैचारिक एवं सांख्यिकीय ढाँचा तथा आँकड़ा संग्रहण प्रणाली पहले से ही मौजूद है, और दूसरी वह श्रेणी है, जहाँ ऐसे ढाँचों को और अधिक विकसित किया जाने की जरूरत है। आँकड़ा अंतरालों में वित्तीय स्थिरता संकेतकों का सुदृढ़ीकरण, गैर बैंक वित्तीय संस्थाओं के संबंध में आँकड़े, वित्तीय संस्थाओं की सीमापार अंतर्संबद्धता, क्षेत्रीय तुलनपत्र, अंतरराष्ट्रीय निवेश और संपत्ति-कीमत आँकड़े शामिल होते हैं। इन लक्ष्यों को व्यापक श्रेणी के आर्थिक एवं वित्तीय सांख्यिकी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो परस्पर संगति रखते हैं, जिससे मापन संबंधी मुद्दों के चलते परस्पर विरोधी संकेतों को विलोपित किया जाता है।

13. रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र से संबंधित इन उपक्रमणों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और इसने आँकड़ा अंतरालों पर ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिनमें भारत को वर्ष 2001 में एसडीडीएस अनुपालनकर्ता के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य शामिल है। उदाहरण के लिए, रिजर्व बैंक वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति और समेकित प्रत्यक्ष एवं संविभाग निवेश के संबंध में आँकड़ों को संकलित करता है और उनकी रिपोर्ट करता है। वर्ष 2011 के लिए भारत की एसडीडीएस से संबंधित वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट, जिसे आईएमएफ के वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है, यह दर्शाता है कि एसडीडीएस वचनबद्धताओं से कोई बड़ा विचलन नहीं हुआ है।

आरबीआई में सांख्यिकी : कुछ आत्मनिरीक्षण

14. एक सरकारी नीति संस्था के रूप में रिजर्व बैंक सांख्यिकी का एक बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। अपने अधिदेश से संगति रखते

¹ युएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, फरवरी 2011 : ड्राफ्ट गाइडलइन्स ऑन इंटेग्रेटेड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स।

हुए हम आँकड़ों का संग्रह और विश्लेषण आंतरिक नीति-निर्माण और बाह्य प्रसार, दोनों के लिए करते हैं। हमारे द्वारा सर्वोत्तम प्रयास किये जाने पर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम उस प्रत्येक वस्तु का मापन और विश्लेषण नहीं करते, जिसका मापन और विश्लेषण करना हमारे लिए आवश्यक होता है। आइए, मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूँ, जहाँ अंतराल को पाटने के लिए रिज़र्व बैंक को वृहत्तर प्रयास करने की जरूरत है।

गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों के संबंध में आँकड़े

15. केंद्रीय बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक का उत्तरदायित्व होता है मौद्रिक कुल राशियों के आँकड़ों का संकलन करना। जबकि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों के संकलन का हमारा कार्य काफी तगड़ा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के आँकड़ों के संकलन की व्याप्ति काफी कम है। यह ऐसा अंतराल है, जिसे हमें पाटना है, क्योंकि वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में एनबीएफसी की भूमिका तेजी से बढ़ती रही है। एनबीएफसी की संख्या वर्ष 2000 में लगभग 8,500 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़ कर 12,500 हो गयी। मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार एनबीएफसी के पास 1.16 ट्रिलियन रुपये मूल्य की आस्तियाँ और 120 बिलियन रुपये की जनता की जमाराशियाँ थीं। एनबीएफसी की निधियों का स्रोत अधिकतर उधार होते हैं, जिनमें से आधे उधार वे बैंकों और अन्य वित्तीय कंपनियों के प्राप्त करती हैं। चलनिधि और ऋण सृजन प्रक्रिया पर एनबीएफसी के प्रभाव की बेहतर समझ रिज़र्व बैंक को हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम एनबीएफसी के संबंध में अधिक व्यापक और आवृत्तिमूलक आँकड़े रखें।

सहकारी बैंकों के संबंध में आँकड़े

16. सहकारी बैंकिंग क्षेत्र कृषि एवं संबद्ध उद्योगों, लघु उद्योगों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को वित्तीय मध्यस्थता सेवाएँ प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत-मार्च 2011 में सहकारी बैंकों की संख्या 97,410 थी, जिनमें से 98 प्रतिशत ग्रामीण सहकारी संस्थाएँ थीं। फिर भी, सहकारी बैंकों के संबंध में हमारे आँकड़े दुर्बल हैं, जो व्याप्ति और रिपोर्टिंग अंतराल, दोनों से ग्रस्त हैं। उनके प्रणालीगत महत्त्व, भौगोलिक पहुँच और वित्तीय समावेशन पर विचार करते हुए रिज़र्व बैंक को नाबार्ड के साथ मिल कर सहकारी बैंकों की सांख्यिकीय आँकड़ा रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन के संबंध में आँकड़े

17. वित्तीय समावेशन रिज़र्व बैंक की नीतिगत प्राथमिकताओं में रहा है। फिर भी, इस तथ्य को समझना कि वित्तीय समावेशन किस प्रकार आरंभिक स्तर पर कार्य करता है, हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। इस संबंध में एक पुस्तक है *पोर्टफोलियो ऑफ दि पुअर* : हाउ

दि वल्ड्स पुअर लिव ऑन 2 डालर्स ए डे (कॉलिन्स एंड अदर्स), जिसे गहरी समानुभूति के साथ लिखा गया है, जो इस बात का संतुलित लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है कि निर्धन लोग किस प्रकार अपने प्रत्येक दिन के वित्त का प्रबंध करते हैं। लेखकों ने सर्वेक्षण के आँकड़ों का संग्रह करने के लिए एक नवोन्मेषी तरीका अपनाया, जिसके लिए उन्होंने बांग्ला देश, भारत और दक्षिण अफ्रीका की गंदी बस्तियों में रहने वाले कंगाल परिवारों का एक पैनल बनाया और एक वर्ष की अवधि के लिए उनकी आमदनी और खर्च की दैनिक डायरी बनायी। इसके बाद उन्होंने एक-एक करके लेन देन का विश्लेषण किया, एक-एक पैसे का हिसाब रखते हुए, ताकि वे यह जान सकें कि निर्धन परिवार अपने धन का प्रबंध किस प्रकार करते हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि अधिकांश गरीब परिवार केवल निर्वाह मात्र नहीं करते हैं। वे आश्चर्यजनक रूप से अनौपचारिक नेटवर्क और पारिवारिक संबंधों से जुड़े परिष्कृत वित्तीय प्रबंध को काम में लाते हुए गरीबी से संघर्ष करते हैं। लेखकों के शब्दों में 'वे रिज़र्व बनाने के लिए धन की बचत करते हैं, जहाँ भी संभव हो, लेनदारों से धन ऐंठते हैं, जब भी संभव हो, परिष्कृत बचत क्लब चलाते हैं, और जहाँ भी उपलब्ध हो, व्यष्टि वित्त का उपयोग करते हैं'।

18. सार्थक वित्तीय समावेशन का अनुसरण करने के लिए रिज़र्व बैंक को देश के बाहर के अनेक अध्ययनों की जरूरत है, जैसे कि 'पोर्टफोलियो ऑफ दि पुअर'। हमें निर्धनों की आमदनी के स्तर और पैटर्न, उनके खर्च करने का पैटर्न, उपभोग और बचत करने की उनकी सीमांतिक प्रवृत्ति, जिन जोखिमों का वे सामना करते हैं, और वे उनसे किस प्रकार निपटते हैं तथा औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से व्यवहार करने में उन्हें क्या लेन-देन लागत आती है, इन सबके बारे में बेहतर समझदारी रखना आवश्यक है।

बासेल III और आर्थिक चक्रों में मोड़ की पहचान करना

19. बासेल III का एक महत्वपूर्ण घटक है प्रतिचक्रीय पूँजी बफर, जो बैंकों को निर्देशित करता है कि अच्छे समय में पूँजी के उच्च स्तर की निर्मित करें, जो उनकी सुरक्षा और सुदृढ़ता के विचार से आर्थिक संकुचन के समय उपयोग में लाया जा सके। वैचारिक रूप से यह स्वच्छ धारणा है, लेकिन इसे परिचालनरत करने में अनेक चुनौतियाँ सामने खड़ी होती हैं, जैसाकि वस्तुतः स्पेन के हाल के अनुभव में देखने को मिला। सर्वप्रथम चुनौती होती है आर्थिक चक्र में मोड़-विंदु की पहचान करना, जो बफर को जारी किये जाने के लिए प्रेरित करता है। इसे वस्तुनिष्ठ और प्रेक्षणीय मानदंडों पर आधारित किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आर्थिक चक्रों पर सुदीर्घ श्रेणी वाले आँकड़ों की भी आवश्यकता है। इसलिए, हमें आर्थिक चक्रों का निर्वचन करने के लिए एक बेहतर डाटाबेस और परिष्कृत सांख्यिकीय कौशल की जरूरत है।

कारपोरेट बचत के संबंध में आँकड़े

20. राष्ट्रीय लेखों के संकलन में, जो सीएसओ का क्षेत्र है, रिजर्व बैंक बचत का अनुमान लगाने, पूँजी प्रवाह के आँकड़ों और बाह्य खातों का संकलन करने की दृष्टि से शामिल होता है। बचत का अनुमान लगाने के लिए मानक प्रथा यह है कि वित्तीय आस्तियों में पारिवारिक बचत का और कारपोरेट बचत का अनुमान लगाया जाये और अवशिष्ट के रूप में भौतिक आस्तियों में परिवार की बचत का निर्धारण किया जाये। अवशिष्ट पद्धति एक मान्य सांख्यिकीय दृष्टिकोण है (इसके लिए जीडीपी का अनुमान भी मध्यवर्ती उपभोग का समायोजन करने के बाद कुल आउटपुट के अवशिष्ट के रूप में किया जाता है)। फिर भी इस पद्धति का तात्पर्य यह होता है कि कारपोरेट बचत के मापन में किसी प्रकार की भूल होने से परिवार की भौतिक बचत का अनुमान लगाने में भूल हो सकती है और इसके चलते समष्टिआर्थिक मूल्यांकन विकृत हो सकता है। कारपोरेट क्षेत्र के संबंध में रिजर्व बैंक का डाटा-सेट व्यापक और समृद्ध है, लेकिन विश्लेषकों द्वारा इसकी परिशुद्धता को चुनौती दी जाती रही है। हमारे लिए इस बात का परीक्षण करना आवश्यक है कि हम किस प्रकार इसमें सुधार कर सकते हैं।

आँकड़ा-संगति

21. रिजर्व बैंक के पास व्यापक अधिदेश है। बहुविध नीतिगत उद्देश्यों का परिणाम बहुविध आँकड़ा प्रणाली हुआ है। इनमें से प्रत्येक आँकड़ा प्रणाली अपने विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार की गयी है और साथ अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनमें सुधार हुआ है। तथापि, समस्या यह रही है कि प्रत्येक आँकड़ा प्रणाली स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। हमें अब अपना ध्यान आँकड़ा प्रणालियों को एकीकृत करने पर केंद्रित करना है, ताकि सभी डाटाबेस की संगति में सुधार हो। यह प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, जिनके खंडों में पारिभाषिक, वैचारिक और व्याप्ति के संदर्भ में वर्षों से परिवर्तन हुए हैं।

आरबीआई में सांख्यिकीय विश्लेषण में अड़चनें

22. उन क्षेत्रों को इंगित करने के बाद, जहाँ रिजर्व बैंक के लिए आँकड़ा अंतराल को भरने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, अब मैं कुछ उन अड़चनों पर चर्चा करना चाहता हूँ, जिनका सामना हम आँकड़ा मापन और निर्वचन में करते हैं।

(i) मुद्रास्फीति का मापन

23. रिजर्व बैंक के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण सांख्यिकी है मुद्रास्फीति की, जो परंपरागत रूप से मापन की समस्या से ग्रस्त रही है। मैं निश्चित रूप से यह स्वीकार करता हूँ कि वैयक्तिक स्तर पर मैं यह नहीं जानता कि मुद्रास्फीति का निर्वचन किस प्रकार किया जाये। बीस वर्ष पहले जब मेरे सिर पर घने बाल थे, मैं बाल बनवाने पर 20 रुपये

खर्च करता था। दस वर्ष पहले, जब मेरे बाल कम होने लगे, तब बाल बनवाने पर मुझे 50 रुपये देने पड़ते थे। और अब, जब मेरे सिर पर बाल नहीं के बराबर हैं, मुझे बाल बनवाने पर 150 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मैं यह निश्चय कर पाने के लिए संघर्षरत हूँ कि इनमें से कितने का संबंध मुद्रास्फीति से है और कितनी प्रीमियम की राशि है, जो मैं नाई को गवर्नर के अस्तित्वहीन बालों की कटाई के लिए देता हूँ।

24. भारत में, हमारे पास मुद्रास्फीति के मापने के अनेक तरीके हैं - एक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और तीन परंपरागत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) हैं। भिन्न-भिन्न सीपीआई आर्थिक संरचना की विषमता और आबादी के विभिन्न खंडों में उपभोग समूह में बड़े अंतर का प्रग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने जनवरी 2011 (आधार 2010 = 100) से एक नयी सीपीआई शृंखला आरंभ की, जिसमें सीपीआई (ग्रामीण), सीपीआई (शहरी) और सीपीआई (संयुक्त) होते हैं, जो पूरे देश के लिए हैं और इनका भारांक डायग्राम वर्ष 2004-05 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित होता है।

25. मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने में जिस एक समस्या से हमें जूझना पड़ता है, वह है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच अपसरण, जो व्याप्ति और भारांक में अंतर के चलते होता है। डब्ल्यूपीआई में खाद्यान्न का भारांक केवल 24 है, जबकि सीपीआई में यह भारांक 37-70 प्रतिशत की सीमा में है। धातुओं और कुछ और अन्य थोक सामानों में, जिनकी कीमतें हाल की अवधि में अस्थिर बनी रही है, का डब्ल्यूपीआई में भारांक 10.7 प्रतिशत है, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सीपीआई में शामिल नहीं किया गया है। सेवाएँ, जिनकी कीमत में बढ़ोतरी होती रही है, सीपीआई में 17-25 प्रतिशत की सीमा में भारांक रखती हैं, लेकिन वे डब्ल्यूपीआई में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। भारांक और व्याप्ति में अंतर और कीमतों के उतार-चढ़ाव में अपसरण न केवल मुद्रास्फीति के विभिन्न मापन के बीच फंदा डालते हैं, बल्कि कभी-कभी उन्हें विपरीत दिशाओं में चलाते हैं।

26. एक अन्य समस्या है कोर मुद्रास्फीति का मापन और निर्वचन। सामान्यतः कोर मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने के लिए वस्तु और सेवाओं के समूह में से खाद्यान्न और ऊर्जा की कीमतों को, जो किसी परिवार के विशिष्ट खर्च का प्रतिनिधित्व करती हैं, अलग कर दिया जाता है। इन्हें बाहर रखने का तर्काधार यह होता है कि खाद्यान्न और ऊर्जा की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव होने की प्रवृत्ति होती है और आपूर्ति पक्ष से इस प्रकार की अस्थिरता को यदि सामान्य मूल्य सूचकांक में अंतरित किया जाये, तो समग्र प्रवृत्ति का निर्वचन करना कठिन हो जाता है। अंदाजा यह है कि कोर मुद्रास्फीति, जो कम अस्थिर होती है, भावी कीमत-प्रवृत्तियों का बेहतर चित्र प्रस्तुत करती है।

27. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी, जहाँ खाद्यान्न और ईंधन उपभोक्ता समूह का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा होते हैं, नीति-निर्माण के लिए कोर मुद्रास्फीति पर ध्यान दिये जाने को चुनौती दी जा रही है। लॉरेंजो बिन स्मागी, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के एक्जिक्यूटिव बोर्ड के सदस्य हैं, तर्क देते हैं कि कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए उत्तम भविष्यकथन करने वाला नहीं होता और वे यह भी कहते हैं कि 'इसे महसूस करने में थोड़ा समय लगा हो सकता है, जैसाकि रोमन लोग कहा करते थे, गलती इनसान से होती है, लेकिन गलती करते रहना शैतानी होती है'²। निस्संदेह, इसके लिए विरोधी तर्क भी प्रस्तुत किये जाते हैं : पॉल क्रुगमैन जैसे अर्थशास्त्री यह तर्क देते हैं कि हेडलाइन मुद्रास्फीति की पूर्वसूचना देने में कोर मुद्रास्फीति की प्रभावोत्पादकता अवधि-विशिष्ट हो सकती है। यदि कोई तीन वर्षों की लंबी कालमान श्रेणी लेता है, तो कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं कि कोर मुद्रास्फीति में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण भविष्यसूचक शक्ति होती है।

28. सैद्धांतिक रूप से, कोर मुद्रास्फीति में अंतर्निहित तर्काधार मान्य होता है, यदि खाद्यान्न और ऊर्जा के उत्पादों की कीमतों में घट-बढ़ अस्थायी हो, और वे, औसतन, अन्य कीमतों में विभेद नहीं रखें। यदि ऐसा नहीं होता है, तो कोर मुद्रास्फीति न तो अंतर्निहित मुद्रास्फीति का बेहतर पूर्वानुमान लगाती है और न ही वह भावी मुद्रास्फीति के बारे में भरोसेमंद भविष्य कथन कर सकती है।

29. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर मुद्रास्फीति के उपयोग और निर्वचन का मुद्दा विवादास्पद बने रहने पर भी, भारत जैसी अर्थव्यवस्था में, हमें कुछ अतिरिक्त सवालों से जूझना पड़ता है। हमारे देश में, जहाँ खाद्यान्न हमारे उपभोग समूह का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा होता है, और ईंधन का भारांक 15 प्रतिशत है, क्या मुद्रास्फीति का मापन, जिसमें इन दोनों को शामिल नहीं किया गया हो, कोर कहा जा सकता है? पिछले तीन वर्षों में ईंधन और कुछ प्रोटीनयुक्त पदार्थों में मुद्रास्फीति निरंतर बनी रही है। क्या किसी निरंतर बने रहने वाले घटक को कोर मापन से बाहर किया जा सकता है?

30. इसके अतिरिक्त, पिछले दशक में हमारी अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों में पण्यों ने अभूतपूर्व माँग का सृजन किया है। आपूर्ति-प्रक्रिया की अनुपस्थिति में इसका परिणाम कीमत के स्तर में स्थायी परिवर्तन हुआ है। अतः, मुद्रास्फीति को हमारे हेडलाइन मापन में कोर मुद्रास्फीति की तुलना में अवश्य ही अधिक उतार-चढ़ाव होगा। रिजर्व बैंक में, हमें हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ावता निर्वचन करते समय इन कारकों से सतर्क रहने की आवश्यकता है।

31. इन वैचारिक और मापन की समस्याओं की पृष्ठभूमि में अब मैं मुद्रास्फीति संकेतकों के संदर्भ में रिजर्व बैंक के विरुद्ध की जा रही कुछ आलोचनाओं का उत्तर देना चाहता हूँ।

32. एक आलोचना यह की जाती रही है कि विश्लेषक इस बारे में उलझन में होते हैं कि रिजर्व बैंक अपनी नीतियों के लिए मुद्रास्फीति के किस मापन का प्रयोग करता है। अतीत में अनेक बार जो कुछ भी हमने इस विषय में कहा था, उसे मैं केवल दुहरा सकता हूँ कि हम मुद्रास्फीति के सभी प्रकार के मापन का अध्ययन करते हैं, हेडलाइन और भिन्न-भिन्न किस्म, दोनों प्रकार की मुद्रास्फीति का, और उनके स्तर का और परिवर्तन-दरों का निर्वचन करने में हम वैचारिक एवं मापन संबंधी कमियों के बारे में सतर्क रहते हैं।

33. एक अन्य आलोचना यह की जाती रही है कि रिजर्व बैंक को डब्ल्यूपीआई की बजाय सीपीआई से निदेशित होना चाहिए। अब जबकि हमारे पास नये सीपीआई आँकड़े हैं, हम इसे स्वागत गतिविधि मानते हैं। सैद्धांतिक रूप से सीपीआई, जो उन वस्तुओं और सेवाओं, जन्हें परिवारों द्वारा उपभोग के लिए क्रय किया जाता है, की कीमतों के सामान्य स्तर में कालक्रम में हुए परिवर्तन का मापन करती है, उसे डब्ल्यूपीआई की तुलना में मुद्रास्फीति का बेहतर मापन माना जाता है। लेकिन, नयी व्यापक सीपीआई का कोई पर्याप्त इतिहास नहीं है, जो आँकड़ा विश्लेषण में सहायक हो और उसे एकमात्र हेडलाइन मुद्रास्फीति के रूप में मापा जा सके। इसके साथ-साथ, रिजर्व बैंक किसी ऐसे मूल्य सूचकांक की उपेक्षा नहीं कर सकता है, जो तर्कसम्मत रूप से सर्वाधिक अद्यतन आर्थिक संरचना को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए, मुद्रास्फीति की स्थिति के हमारे मूल्यांकन में हम नये सीपीआई का और परंपरागत सीपीआई का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अकेले उन्हीं का नहीं।

34. यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि डब्ल्यूपीआई त्रुटिहीन होता है। अपनी वर्तमान संरचना में डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमत में उतार-चढ़ाव का प्रग्रहण नहीं करता है। यह भी कि, यह उपभोक्ता और उत्पादक द्वारा बतायी गयी कीमतों का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए, इस सूचकांक में दूध जैसी महत्वपूर्ण वस्तु की कीमत का प्रग्रहण खुदरा बजार से किया जाता है, न कि उत्पादक के स्तर से। सीपीआई के विपरीत, उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीसीआई) विक्रेता के परिप्रेक्ष्य से कीमत परिवर्तन का मापन करता है। विक्रेताओं और क्रेताओं की कीमतों में अंतर सरकारी उपदान, बिक्री और उत्पाद शुल्क, तथा वितरण लागत के चलते होता है। इसलिए, इन कारणों को देखते हुए यह वांछनीय है कि हम ऐसे सीपीआई को विकसित करें, जो कालक्रम में घरेलू सामान और सेवाओं की बिक्री-कीमतों में हुए औसत परिवर्तन का मापन करे।

² लॉरेंजो बिन स्मागी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के एक्जिक्यूटिव बोर्ड के सदस्य, जून 2011

(ii) व्यय-पक्ष जीडीपी अनुमान से संबंधित मुद्दे

35. मौद्रिक नीति के प्रयोजनार्थ यह महत्वपूर्ण होता है कि जीडीपी आँकड़ों का अध्ययन करके सकल माँग-स्थिति का मूल्यांकन किया जाये। अपनी सुपरिचित सीमाओं के बावजूद व्यय पक्ष जीडीपी आँकड़ों का उपयोग सकल माँग-पक्ष के घटकों के लिए प्रॉक्सियों के रूप में किया जा रहा है। तथापि, हाल की तिमाहियों में जीडीपी आँकड़ों के अभिज्ञात घटकों के बीच विभेद, जिसका मापन आउटपुट विधि और व्यय विधि द्वारा किया जाता है, बढ़ा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही के लिए व्यय-पक्ष के आँकड़े में यदि हम निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार का अंतिम उपभोग व्यय, सकल पूँजी निर्माण और निवल निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को जोड़ दें, तो हमें 9 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के आँकड़े मिलते हैं। लेकिन आपूर्ति-पक्ष से व्युत्पन्न वृद्धि दर में करों को जोड़ने और आर्थिक सहायता से प्राप्त आय को घटाने पर हमें यह आँकड़ा 5.6 प्रतिशत मिलता है। दोनों आँकड़ों के बीच का अंतर, जो जीडीपी के 3.4 प्रतिशत पर ऊँचा है - वह भूल वाला घटक होता है। भूल वाला ऐसा घटक न केवल आँकड़ों को अपारदर्शी बना देता है, बल्कि सकल माँग के मूल्यांकन को जटिल बना देता है।

36. यह संभवतः मेरे लिए एक उपयुक्त संदर्भ है कि मैं कुछ सरकारी आँकड़ों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करूँ। आर्थिक माप, यथा, आमदनी, कर्ज, घाटा और भुगतान संतुलन उत्तम बहीखाता और लेखांकन प्रणालियों की प्राथमिक प्रशाखा होते हैं। इन आँकड़ों में अनेक वैरिएबलों का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग किया जाता है और धारणाओं को सरल बनाया जाता है। ऐसा अंशतः इसलिए, क्योंकि प्रत्येक रिकार्ड को रखना या उसका संसाधन करना महंगा और समय-सापेक्ष होता है। इसका कारण यह भी है कि इन वैरिएबलों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता है; अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विशाल असंगठित अनौपचारिक खंड के बारे में सोचिए।

37. हम इसका सामना किस प्रकार करते हैं? आँकड़ों का एक भाग नियमित सर्वेक्षण करके पूरा किया जाता है। लेकिन सर्वेक्षणों में नमूना चयन संबंधी भूलें होती हैं। यह भी कि, आर्थिक चक्र, खास कर आर्थिक मंदी, आर्थिक संकेतकों की परिशुद्धता के प्रति महत्वपूर्ण चुनौती खड़ी करते हैं, जिनमें वे संकेतक शामिल हैं, जिनका उपयोग स्रोत आँकड़ों के रूप में आरंभिक जीडीपी अनुमान के लिए किया जाता है। इस अवधि के दौरान, कुछ फर्मों अपना कारोबार बंद कर देती हैं, कुछ केवल आरंभिक रूप से सर्वेक्षण पूरा करती हैं और कुछ स्वैच्छिक सर्वेक्षणों का उत्तर देना नहीं चाहती हैं। इसलिए, किस खाते में क्या जाता है, इसका पता करने के लिए भरोसेमंद और सही कार्यप्रणाली की खोज करना, आजकल की प्रौद्योगिकी के साथ

भी, कोई हलका काम नहीं है, विशेष रूप से एक आधुनिक, जटिल अर्थव्यवस्था के लिए।

(iii) संभावित आउटपुट का अनुमान लगाना

38. केंद्रीय बैंक के लिए संभावित आउटपुट का सही-सही अनुमान लगाना काफी महत्वपूर्ण होता है, ताकि वह माँग की स्थिति और आउटपुट अंतराल का मूल्यांकन कर सके। इसके लिए विश्वसनीयता और समयनिष्ठता महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, एक आउटपुट अंतराल संबंधी गलती से फेडरल रिजर्व ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया, जिसके चलते 1970 के दशक की विश्वव्यापी मुद्रास्फीति हुई।³

39. संभावित जीडीपी का प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में अनुमान सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करते हुए लगाया जाता है। इस प्रकार का कोई अनुमान तीन मुख्य कारणों से भूल का कारण बनता है। पहला और स्पष्ट कारण यह है कि जीडीपी के आँकड़े को अक्सर संशोधित किया जाता है - कभी-कभी काफी संशोधन किया जाता है - जब आरंभिक अनुमान प्रकाशित कर दिये गये होते हैं। दूसरा, किसी भी समय उत्पादकता वृद्धि के स्तर में काफी अनिश्चितता होती है। अंत में, संभावित जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए कोई व्यापक रूप से सहमत धारणा या कोई विशिष्ट कार्यप्रणाली विद्यमान नहीं होती है। भारत के मामले में ये कारण और अधिक प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार के संबंध में व्यापक और सुसंगत आँकड़ों की कमी होती है।

40. आर्थिक कार्यकलाप के हर्द-गिर्द अनिश्चितता संकट-पश्चात् अवधि में बढ़ गयी है। भारत इसका अपवाद नहीं है। भारत की संभावित वृद्धि का मूल्यांकन करना, जो न्यून और स्थिर मुद्रास्फीति के हमारे उद्देश्य के अनुरूप है, एक चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2009-10 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने यह बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संभावित आउटपुट, जो संकट-पूर्व अवधि में 8.5 प्रतिशत था, वह संकट-पश्चात् अवधि में गिर कर 8.0 प्रतिशत हो गया हो सकता है। मानक निस्यंदन तकनीक का अनुसरण करते हुए नवीनतम मूल्यांकन बताता है कि संभावित आउटपुट वृद्धि और अधिक गिर कर लगभग 7.5 प्रतिशत हो गयी हो सकती है।

(iv) बाजार संदर्भ दरें

41. हाल के लिबोर विवाद ने दुनिया का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि किस प्रकार कुछ बड़ी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं ने अभिकथित रूप से एक सामान्यतः प्रयुक्त बाजार दर को प्रभावित किया है।

³ ऑफेनाइड्स, ए (2001) : 'मॉनेटरी पॉलिसी रूल्स बेस्ड ऑन रियल टाइम डाटा'। अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 91, 964-985।

42. क्या भारत में लिबोर की तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है? भारत में लिबोर का प्रतिरूप कुछ कम प्रयुक्त माइबोर है, जो फिम्डा-एनएसई द्वारा निश्चित किया जाता है। रिजर्व बैंक अपनी ओर से, प्रत्येक दिन एक पारदर्शी सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग करते हुए हाजिर यूएसडी-आइएनआर और हाजिर इयूआर-आइएनआर की संदर्भ विनिमय दरों का संकलन और प्रकाशन करता है। इससे पूर्व, हम प्रत्येक कार्य दिवस को 12 बजे दोपहर में कुछ चुनिंदा बैंकों से ली गयी बिड /ऑफर दरों के माध्य का औसत निकाल कर दर निश्चित किया करते थे। कुछ महीने पहले हमने इस पद्धति को बदल दिया। अब हम 11.45 बजे पूर्वाह्न और 12.15 बजे अपराह्न के बीच यादृच्छिक रूप से चुने गये 5 मिनटों में दर घोषित करने वाले बैंकों की चयनित सूची से दर प्राप्त करते हैं और संदर्भ दर 12.30 बजे अपराह्न में प्रकाशित करते हैं। ऐसे बैंकों का चयन घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में उनके बाजार हिस्से और प्रतिनिधि स्वरूप के आधार पर किया जाता है। रिजर्व बैंक बैंकों का चयन करने की क्रियाविधि की और मत प्राप्त करने की कार्यप्रणाली की समीक्षा आवधिक तौर पर करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संदर्भ दर बाजार के कार्यकलाप का सत्य प्रतिबिंब प्रस्तुत करती रहे।

(v) आँकड़ा निर्वचन : आँकड़ों के पीछे देखने की जरूरत

43. सूचना प्रौद्योगिकी ने आँकड़ों की उपलब्धता में सुधार किया है। विरोधाभासी रूप से इसने आँकड़ों के गलत निर्वचन की संभावना को भी बढ़ा दिया है। अपनी हाल की पुस्तक 'थिंकिंग फास्ट एंड स्लो' में डैनियल काह्नमैन स्पष्ट करते हैं कि कहाँ हम अपनी सहज बुद्धि पर विश्वास कर सकते हैं और जहाँ नहीं और हम धीमी सोच के फायदे किस प्रकार उठा सकते हैं।

44. एक उदाहरण पर विचार करें : हाल ही में एक दैनिक वित्तीय समाचार-पत्र में पिछली तिमाही में भारतीय कंपनियों के परिचालन परिणामों पर आधारित एक विश्लेषण में दावा किया गया है कि ब्याज पर किया गया व्यय उनके राजस्व का 11.1 प्रतिशत था और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि रिजर्व बैंक की दर में कटौती से इन फर्मों की लाभ की संभावना में काफी अंतर होगा।⁴ गणितीय दृष्टि से यह सही है और पाठकों को विश्वास करायेगा कि ब्याज की उच्च लागत ने लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। पाठक अपनी सहज बुद्धि से वर्ष 2011-12 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि में गिरावट होकर उसके 6.5 प्रतिशत हो जाने का कारण मार्च 2010-अक्टूबर 2011 के दौरान रिजर्व बैंक की नीति-दरों को 375 आधार

अंक बढ़ाया जाना मानेंगे। लेकिन इसी नमूने को निकट से जाँचने पर यह पता चलेगा कि इस विश्लेषण के लिए प्रयुक्त आँकड़ों में वित्तीय और बीमा फर्मों शामिल हैं, जिनका विक्रय में ब्याज का अनुपात 65 प्रतिशत तक ऊँचा होता है। इसके विपरीत, गैर वित्तीय फर्मों, जो कारोबार के 85 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेवार होती हैं, उनका ब्याज-खर्च विक्रय का केवल 2.7 प्रतिशत होता है। अतः, यह आवश्यक है कि आँकड़ों के पीछे देखा जाये और इस बात की खोज की जाये कि नीचे क्या है।

45. एक अन्य वैरिएबल पर विचार करें - वास्तविक ब्याज दर। रिजर्व बैंक में किये गये अनुसंधान से पता चलता है कि वास्तविक ब्याज दर और निवेश कार्यकलाप एक दूसरे से प्रतिलोम संबंध रखते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या निवेश में मंदी आने के पीछे उच्च वास्तविक ब्याज दर एकमात्र कारण होता है?

46. हाल ही में, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत प्रभावी उधार दरों (डब्ल्यूएलआर) के विस्तृत कालमान श्रेणी आँकड़े प्रकाशित किये हैं, जिनका संकलन वर्ष 1992-93⁵ से अलग-अलग ऋण खातों के संविदागत ब्याज ब्यौरों के आधार पर किया गया था। डब्ल्यूएलआर की प्रवृत्ति यह स्पष्ट दर्शाती है कि आज वास्तविक उधार ब्याज दर वर्ष 2007-08 की उच्च वृद्धि अवधि, जब निवेश में उछाल आया था, की तुलना में कम है। स्थिति यही है, भले ही हम डब्ल्यूपीआई या जीडीपी अपस्फीतिकारक का प्रयोग करें।

47. कुछ विश्लेषकों ने वास्तविक उधार दर निकालने के लिए बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक के मूल्यांकन की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया है। इस विश्लेषण के लिए बीपीएलआर का उपयोग त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण इसलिए कि बैंकों के बीपीएलआर उधार दरों की न्यूनतम सीमा बनने में विफल रहे : वाणिज्यिक बैंकों का 60-70 प्रतिशत से अधिक उधार बीपीएलआर से कम दर पर दिया गया। यही कारण था कि रिजर्व बैंक ने बीपीएलआर के स्थान पर आधार दर को लागू किया। बीपीएलआर व्यावहारिक रूप से सार्थक संदर्भ दर के रूप में पुराना पड़ चुका है और इसीलिए बीपीएलआर से व्युत्पन्न वास्तविक उधार दरों में स्पष्टतः कृत्रिम रूप से ऊँचा रहने की प्रवृत्ति होगी।

48. रिजर्व बैंक का कहना है कि ब्याज की लागत उन अनेक कारकों में से एक कारक है, जिन्होंने वृद्धि को मंद किया है, और रिजर्व बैंक द्वारा नीति-दर का बढ़ाया जाना अकेले निवेश में मंदी को स्पष्ट नहीं कर सकता है। मैंने अपने आर्थिक अनुसंधान विभाग को कहा है कि

⁵ मोहंती, दीपक, ए.बी.चक्रवर्ती और गंगाधरण (2012), मेजर ऑफ नॉमिनल एंड रियल इफेक्टिव लेंडिंग रेट्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक, वर्किंग पेपर सिरीज, मई

⁴ बिजनेस स्टैंडर्ड, 5 जुलाई 2012 (पृ.11)

वह वास्तविक ब्याज दर और निवेश कार्यकलाप के बीच कालमान श्रेणी संबंध का अध्ययन करे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले दो महीनों में हम पब्लिक डोमेन में उस रिपोर्ट को रख पायेंगे।

समाहार

49. अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने संकट के संदर्भ में सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में बात की है और यह भी कहा है कि किस प्रकार प्रत्येक बड़े आर्थिक और वित्तीय संकट ने आँकड़ा मानकों में और सांख्यिकीय विश्लेषण के साधनों में सुधार किया है। मैंने चालू वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अभिज्ञात आँकड़ा अंतरालों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का उल्लेख किया। इसके बाद मैंने रिजर्व बैंक के भीतर कुछ महत्वपूर्ण आँकड़ा अंतरालों की छानबीन की और इस तथ्य को आलोकित किया कि उन्हें सुधारना क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद, मैंने आँकड़ा मापन और निर्वचन में कुछ अंतरालों की चर्चा की, और जहाँ भी आवश्यक और संभव हुआ, यह इंगित किया कि किस प्रकार हम इन अवरोधों पर ध्यान दे सकते हैं।

50. निष्कर्षतः, मैं इस बात को दुहराना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक स्वयं को एक सुविज्ञ संस्था के रूप में स्थापित करने के बारे में काफी सजग है। हम समयनिष्ठता और परिशुद्धता के साथ और कौशल सेटों में आँकड़ों का संचय करते हैं, ताकि उन आँकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन किया जा सके। अक्सर, वास्तविक जगत की जटिल समस्याएँ हमारे आँकड़ा सेटों की पर्याप्तता और सत्यता का और उनका विश्लेषण और निर्वचन करने की हमारी योग्यता की जाँच-परख करती है। हम अपने आँकड़ा-संग्रहण में सुधार के लिए भरसक सुधार करते हैं और उनका विश्लेषण करते समय वैचारिक और मापन संबंधी भूलों के बारे में सतर्क रहते हैं।

51. अंत में, मैं एक बार फिर हमारे बाह्य विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस वार्षिक सांख्यिकी सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।

संदर्भ

बोरियो, क्लॉडियो : दि फाइनेंशियल क्राइसिस : ह्याट इम्प्लिकेशन्स फॉर न्यू स्टैटिस्टिक्स? इरविंग फिशर समिति सम्मेलन के लिए बीआइएस भाषण, अगस्त।

सी.आर.राव (1997) : *स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रुथ : पुटिंग चान्स टू वर्क*, वर्ल्ड साइंटिफिक पब्लिकेशन।

कॉलिन्स डैरिल, जोनाथन मोर्डक, स्टुअर्ट रदरफोर्ड, ऑरलैंडा रुथवेन (2009) : *पोर्टफोलियो ऑफ दि पुअर : हाउ दि वर्ल्ड्स पुअर लिव ऑन 2 डॉलर्स ए डे*, प्रिन्सटन युनिवर्सिटी प्रेस, अप्रैल 20।

युरोपियन सेंट्रल बैंक (2010) : सेंट्रल बैंक स्टैटिस्टिक्स- ह्याट डिड दि फाइनेंशियल क्राइसिस चेंज? सांख्यिकी के संबंध में पाँचवाँ ईसीबी सम्मेलन, अक्टूबर 19-20।

काह्लमैन, डेनियल (2011) : *थिंकिंग फास्ट एंड स्लो*, प्रकाशक : फर्रार, स्ट्रॉस और जिरॉक्स : पहला संस्करण (अक्टूबर 25)।

क्रुगमैन, पॉल (2011) : हेडलाइन बनाम कोर इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल टाइम्स, 2 जून।

लॉरेन्जो बिनि स्मागी (2011) : इग्नोरिंग दि कोर कैन कीप इन्फ्लेशन ऐट बे, फाइनेंशियल टाइम्स, 1 जून।

मोहंती, दीपक, ए.बी.चक्रवर्ती और एस.गंगाधरण (2012) : 'मेजर्स ऑफ नॉमिनल एंड रियल इफेक्टिव लेंडिंग रेट्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया', *भारतीय रिजर्व बैंक वर्किंग पेपर सिरीज*, मई।

ऑर्फेनाइड्स, ए (2001) : 'मॉनेटरी पॉलिसी रूल्स बेस्ड ऑन रियल-टाइम डाटा', *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू*, 91, 964-985

पोनप्पा श्याम (2012) : डिसिजन एनेलिसिस फॉर इंटररेस्ट रेट्स : दि गवर्नमेंट शुड यूज रियलिस्टिक सिनेरियोज ह्वेन डिसाइडिंग मॉनेटरी पॉलिसी - एंड अदर पॉलिसी फॉर दैट मैटर, *बिजनेस स्टैंडर्ड*, 5 जुलाई।

सिम्स, सी.ए. (2011) : स्टैटिस्टिकल मॉडेलिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स इफेक्ट्स, नोबेल लेक्चर, दिसंबर।

तालेब नसीम निकोलस (2008) : *फुल्ल बाइ रैंडमनेस : दि हिडेन रोल ऑफ चान्स इन लाइफ एंड इन दि मार्केट्स*, योर कोच दि ए बॉक्स : दूसरा संस्करण, 2 सितंबर।

युएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, फरवरी 2011 : ड्राफ्ट गाइडलाइन्स ऑन इंटेग्रेटेड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स।